



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

WESTERN ZONE BENCH,

Original Application No. 13/2023 (WZ)

Book No : 1123
PAGE : 143/23
SR. NO. : 1133/23
DATE : 28/06/23

M. N. J.
MANGLAGAURI P. MAKWANA
NOTARY
GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

Rambahadur Hoslaprasad Yadav

...Applicant(s)

Versus

State of Gujarat & Ors.

...Respondent(s)

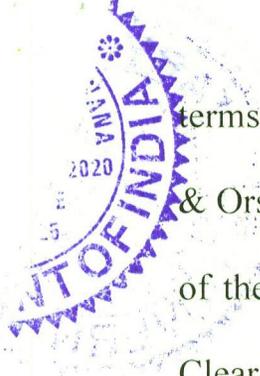
COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (RESPONDENT No. 1)

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

I Dr. Yogesh Kumar, currently working as Scientist 'C', at the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Dr. Yogesh Kumar in my official capacity in the Ministry Environment, Forest and Climate Change, i.e., Respondent No.5 in the above mentioned matter, I am conversant with the facts and circumstances of the case on the basis of official records, and as such authorized and competent to swear this affidavit.
2. It is submitted that a short affidavit is being filed by the answering respondent at this stage and craves leave and liberty to file a detailed Counter Affidavit to the aforesaid application, as and when required.
3. That the applicant is aggrieved by the illegal mining of the ordinary sand from the riverbeds of the State of Gujarat in violation of the Judgement passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Deepak Kumar Vs. State of Haryana and in

Yogesh Kumar
28/06/23



terms of Judgment passed by this Hon'ble Tribunal in Satendra Pandey Vs. MoEF & Ors. The applicant has further stated that the mining operations in the riverbeds of the State of Gujarat are being carried out on the basis of the Environmental Clearances (EC) granted by District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA).

4. That it is reiterated that the Answering Respondent issued a notification S.O. 1886 (E) vide dated 20.04.2022 wherein, Environmental Clearances of all minor mineral irrespective of mine lease area shall be dealt at the level of State Level Impact Assessment Authority (SEIAA). The said notification is in compliance to the (i) Deepak Kumar judgment, (ii) NGT order dated 13.09.2018 and (iii) the OM dated 12.12.2018. A Copy of the Ministry's Notification S.O. 1886 (E) dated 20.04.2022 is marked and annexed herein as **ANNEXURE R5/1**.
5. It is submitted that, the Hon'ble Tribunal vide order dated 07.12.2022 in the matter of Jayant Kumar Vs. Ministry of Environment Forest and Climate Change & Ors. in Original Application No. 142 of 2022 has directed the Ministry to apprise the Tribunal regarding the re-appraisal of the Environmental Clearances issued by DEIAA to be done by SEIAA.
6. It is humbly submitted that in compliance to the order passed by the Hon'ble Tribunal vide dated 07.12.2022, this Ministry issued an Office Memorandum F. No. IA 3-22/11/2023-IA.III dated 28.04.2023, where all the valid ECs issued by DEIAA (between 15.01.2016 to 13.09.2018) shall be re-appraised through SEAC/SEIAA. The OM also specifies that scrutiny and appraisal of such ECs shall be based on the checklist provided therein. It is further submitted that Environmental Clearances (EC) granted by District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) from 15.01.2016 to 13.09.2018 will continue to be valid for one year as per the Ministry's OM dated 28.04.2023, subject to the compliance of the conditions prescribed therein. A Copy of the OM F. No. IA3-

Gurur
24/06/23

22/11/2023-IA.III (E-208230) dated 28.04.2023 is marked and annexed herein as

ANNEXURE R5/2.

7. That it is respectfully submitted that State Department of Mines and Geology is the Nodal Authority in the State for dealing with the allotment of mining leases under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDR Act) and is entrusted with the enforcement and regulation of mining operations in a State including illegal mining. Further, the State Government is empowered under Section 23 C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957(MMDR Act) to make rules for prevention of illegal mining, transportation and storage of minerals and the State Department of Mines & Geology is the Nodal Authority in the State for dealing with the allotment of mining leases under the MMDR Act and is entrusted with the enforcement and regulation of mining operations in a state.
8. It is humbly submitted that, the State Pollution Control Board is the Nodal Authority in the State for dealing with cases related to pollution or environment management coming under the purview of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act 1986.
9. That in view of the aforementioned facts and circumstances, this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to pass appropriate order(s).



डॉ. योगेश कुमार / Dr. Yogesh Kumar
वैज्ञानिक 'सी' / Scientist 'C'

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
भारत सरकार / Govt. of India

ए. के. का., गाँधीनगर (गुजरात) / IRO, Gandhinagar(Gujarat)

VERIFICATION

Verified at Gandhinagar on 28th day of June, 2023 that the contents of this affidavit based on official record(s) maintained and information available in the office are true and correct, no part of it is false and nothing has been concealed there from.

Yogesh Kumar
28/06/23

DEPONENT

डॉ. योगेश कुमार / Dr. Yogesh Kumar
वैज्ञानिक 'सी' / Scientist 'C'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
भारत सरकार / Govt. of India
ए. के. का., गाँधीनगर (गुजरात) / IRO, Gandhinagar(Gujarat)

**SOLEMNLY AFFIRMED
BEFORE ME**

m.n

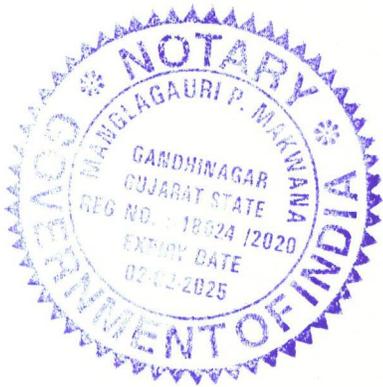
**MANGLAGAURI P. MAKWANA
NOTARY
GOVT. OF INDIA**

IDENTIFIED BY ME

ADVOCATE

Name :
Sanad No. G.....

28 JUN 2023





भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235241
CG-DL-E-20042022-235241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1795]
No. 1795]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

का.आ. 1886(अ).—केंद्रीय सरकार पर्यावरण और वन विभाग के पूर्ववर्ती मंत्रालय में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है), परियोजनाओं की कतिपय प्रवर्ग के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी आज्ञापक बनाने के लिए, संख्या का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की है।

और राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) का गठन प्रवर्ग ख के अधीन सभी प्रस्तावों के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) पर विचार और अनुदान के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राज्य स्तर पर ईआईए अधिसूचना, 2006 के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किया गया है;

और राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण ने पर्यावरण मंजूरी मूल्यांकन प्रक्रिया में पिछले पंद्रह वर्षों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी प्रस्तावों के कुशल और पारदर्शी निपटान के लिए परिवेश पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है;

और केंद्रीय सरकार राज्य स्तर पर मंजूरी की प्रसुविधा के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को और विकेंद्रीकृत करना आवश्यक समझती है;

और आज की तारीख में, सुरक्षा भागीदारी के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ राष्ट्रीय रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित प्रवर्ग ख की परियोजनाओं का राज्य स्तर पर भी मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसे केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक समझती है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात्, लोकहित में भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(1) पैरा 4 में, उप-पैरा (iii) क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

(iii) क) राष्ट्रीय रक्षा या सामरिक या सुरक्षा महत्व से संबंधित हैं या जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा संकटकाल जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं को अधिसूचित किया गया है या राष्ट्रीय कार्यक्रमों या स्कीमों या मिशन या ऐसी परियोजनाओं के अधीन पर्यावरण के अनुकूल क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए जो इस अधिसूचना में यथा अधिकथित समय-सीमा से अधिक विलंबित हैं और समय-समय पर इस संबंध में यथा-अधिकथित मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें केंद्रीय स्तर पर प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के रूप में विचार किया जाएगा;

(2) अनुसूची में, -

(i) मद 1(क) के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, -

(क) गैर-कोयला खनन पट्टे के संबंध में "> 100 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"कोयले के अलावा अन्य प्रमुख खनिज खनन पट्टे के संबंध में >250 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र";

(ख) ">150 हेक्टेयर" प्रतीक, अंक और अक्षर के स्थान पर, "> 500 हेक्टेयर" प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (4) में, -

(क) गैर-कोयला खनन के संबंध में <100 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र के स्थान पर,

पट्टा", निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"लघु खनिज खनन पट्टों के संबंध में सभी खनन पट्टा क्षेत्र और कोयले के अलावा अन्य प्रमुख खनिज खनन पट्टे के संबंध में <250 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र";

(ख) "<150 हेक्टेयर" के प्रतीकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "<500 हेक्टेयर" के प्रतीक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) मद 1(ग) के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, -

(क) क्रम संख्या (i) में, "> 50 मेगावाट, प्रतीकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "> 100 मेगावाट" प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, -

(क) क्रम संख्या (i) में, "<50 मेगावाट" प्रतीक, अंक और अक्षर के स्थान पर, "<100 मेगावाट" प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या (ii) में, -

(I) "और <50,000 हेक्टेयर" शब्द, प्रतीक और अंक का लोप किया जाएगा;

(II) बिंदु (ग) में सारणी में, "से <50,000" शब्द, प्रतीक और अंक का लोप किया जाएगा; ।

(ग) स्तंभ (5) में, क्रम संख्या (ii) के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) अंतर-राज्यीय मुद्दों से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर श्रेणी में परिवर्तन के बिना किया जाएगा";

(iii) मद 1(घ) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, "> 50 मेगावाट" प्रतीकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "> 100 मेगावाट" प्रतीकों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, "<50 मेगावाट" प्रतीक, अंक और अक्षर के स्थान पर, "<100 मेगावाट" प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) मद 2(क) के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, ">1" प्रतीकों और अंक के स्थान पर, ">2.5" प्रतीकों और अंक को रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, "<1" प्रतीकों और अंक के स्थान पर, "< 2.5" प्रतीक और अंक रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (5) में, विद्यमान पैरा के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर स्थित धुलाई मशीनों के साथ एकीकृत कोयला खनन परियोजनाओं को कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विद्यमान सीमा के अनुसार केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर पर, यथास्थिति, विचार किया जाना जारी रहेगा";

(v) मद 2 (ख) के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, "<0.5 मिलियन टीपीए का उत्पादन" प्रतीक, अंक, शब्द और अक्षर के स्थान पर, "सभी खनिज परिष्करण परियोजना, परिष्करण की प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (5) में, विद्यमान पैरा के पश्चात, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा,

अर्थात्: -

"भीतर स्थित लाभकारी संयंत्रों के साथ एकीकृत खनन परियोजनाएं खनन पट्टा क्षेत्र पर केन्द्रीय स्तर पर विचार किया जाता रहेगा या यथास्थिति, राज्य स्तर, खनन परियोजनाओं के लिए विद्यमान सीमा के अनुसार।";

(vi) मद 7 (क) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, "सभी परियोजनाओं" शब्दों के स्थान पर "सभी नई परियोजनाएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (4) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"सभी विस्तार परियोजनाएं, जिनमें हवाई पट्टियां भी सम्मिलित हैं, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं।"

[फा. सं. आईए 3-22/10/2022-आईए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड III, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 1807(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2022

S.O. 1886(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

And whereas, the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) have been constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for implementation of the EIA Notification, 2006 at State level for exercising delegated powers to consider and grant Environmental Clearance (EC) for all proposals under Category B;

And whereas, the SEIAAs have gained substantial experience over the past fifteen years in the EC appraisal process and the process at the State level has also been made completely online through the PARIVESH portal for efficient and transparent disposal of EC proposals;

And whereas, the Central Government deems it necessary to further decentralise the EC process for facilitating clearances at State level;

And whereas, as on date, category 'B' projects, relating to national defence and strategic importance with significant element of security involvement are also being appraised at the State level which, the Central Government deems it necessary to be appraised centrally taking into account national security concerns;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(1) in paragraph 4, for sub-paragraph (iii a), the following shall be substituted, namely:-

(iii a) Such Category 'B' projects, relating to the National defence or strategic or security importance or those as notified by the Central Government on account of exigencies such as pandemics, natural disasters or to promote environmentally friendly activities under National Programmes or Schemes or Missions or such projects which are inordinately delayed beyond the stipulated timeline as laid down in this notification and also meet the criteria as laid down in this regard from time to time, shall be considered at the Central level as Category 'B' projects;

(2) in the Schedule,-

(i) against item 1(a),-

(a) in column (3),-

(A) for ">100 ha. of mining lease area in respect of non-coal mining lease", the following shall be substituted, namely:-

>250 ha mining lease area in respect of major mineral mining lease other than coal";

(B) for the symbol, figures and letters "> 150 ha", the symbol, figures and letters "> 500 ha" shall be substituted;

(b) in column (4),-

(A) for "≤ 100 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease", the following shall be substituted, namely:-

"All mining lease area in respect of minor mineral mining leases and ≤ 250 ha mining lease area in respect of major mineral mining lease other than coal";

- (B) for the symbols, figures and letters “ ≤ 150 ha”, the symbols, figures and letters “ ≤ 500 ha” shall be substituted;
- (ii) against item 1(c),—
- (a) in column (3),—
- (A) in serial number (i), for the symbols, figures and letters “ ≥ 50 MW”, the symbols, figures and letters “ ≥ 100 MW” shall be substituted;
- (B) serial number (ii) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in column (4),—
- (A) in serial number (i), for the symbol, figures and letters “ < 50 MW”, the symbol, figures and letters “ < 100 MW” shall be substituted;
- (B) in serial number (ii),—
- (I) the word, symbol and figures “and $< 50,000$ ha.” shall be omitted;
- (II) in point (c) in the table, the word, symbol and figures “to $< 50,000$ ” shall be omitted;
- (c) in column (5), after serial number (ii), the following serial number shall be inserted, namely:—
- “(iii) Irrigation projects involving Inter-State issues shall be appraised at Central level without change in category.”;
- (iii) against item 1(d),—
- (a) in column (3), for the symbols, figures and letters “ ≥ 50 MW”, the symbols, figures and letters “ ≥ 100 MW” shall be substituted;
- (b) in column (4), for the symbol, figures and letters “ < 50 MW”, the symbol, figures and letters “ < 100 MW” shall be substituted;
- (iv) against item 2(a),—
- (a) in column (3), for the symbols and figure “ ≥ 1 ”, the symbols and figures “ ≥ 2.5 ” shall be substituted;
- (b) in column (4), for the symbols and figure “ < 1 ”, the symbols and figures “ < 2.5 ” shall be substituted;
- (c) in column (5), after the existing paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:—
- “Integrated coal mining projects with washeries located within mining lease area shall continue to be considered at Central level or State level, as the case may be, as per the extant threshold for coal mining projects.”;
- (v) against item 2 (b),—
- (a) in column (3), the existing entries shall be omitted;
- (b) in column (4), for the symbol, figures, words and letters “ < 0.5 million TPA throughput”, the words “All mineral beneficiation projects irrespective of the procedure for beneficiation” shall be substituted;
- (c) in column (5), after the existing paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:—
- “Integrated mining projects with beneficiation plants located within mining lease area shall continue to be considered at Central level or State level, as the case may be, as per the extant threshold for mining projects.”;
- (vi) against item 7 (a),—
- (a) in column (3), for the words “All projects”, the words “All new projects” shall be substituted;

(b) in column (4), the following shall be inserted, namely:—

“All expansions projects, including airstrips, which are for commercial use.”.

[F. No. IA3-22/10/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section III, sub-section (ii), vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended, vide, the notification number S.O. 1807(E), dated the 12th April, 2022.

F. No. IA3-22/11/2023-IA.III (E-208230)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

3rd Floor, Vayu Wing
Indira Paryavaran Bhavan,
Jor Bagh Road,
New Delhi-110003

Dated: 28th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Compliance of order dated 07.12.2022 passed by Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022 in the matter of Jayant Kumar vs. Ministry of Environment, Forests and Climate Change - reg.

The Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench), New Delhi vide order dated 13.09.2018 in O.A. No. 186 of 2016 (Satendra Pandey vs Ministry of Environment Forest & Climate Change & Anr) had observed that the Ministry's Notification S.O. 141(E) dated 15.01.2016 was not in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in the matter of Deepak Kumar Vs. State of Haryana and Others and passed certain directions.

2. In the above case, Hon'ble NGT had *inter-alia* directed that mining projects with lease areas of 0 to 5 ha are to be evaluated by State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) for recommendation and grant of Environmental Clearance (EC) by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) instead of District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA). In compliance of the said directions, Ministry issued an OM dated 12.12.2018 addressed to Chief Secretaries of all the States/UTs directing to comply with the directions of Hon'ble NGT.

3. Subsequently, Hon'ble NGT vide its order dated 07.12.2022 in O.A.142 of 2022 in the matter of Jayant Kumar vs. Ministry of Environment, Forests and Climate Change *inter-alia* observed that "mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2016 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (*supra*) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental

clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986."

4. The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM. The State Government may assess the existing workload of SEAC(s) and accordingly, send proposals for constitution of additional SEAC for a specified period to deal with such additional workload.
5. Further, in order to have a uniform approach across the country for such appraisal, SEIAA shall scrutiny and appraise the proposals based on the checklist provided below:
 - i. Completely filled up Form-2 as per Ministry's OM dated 15.12.2021.
 - ii. Pre-Feasibility Report (PFR) as per MoEF Guidelines dated 30.12.2010
 - iii. Valid Mine Lease Document
 - iv. Approved Mining Plan from the concerned Authorities
 - v. District Survey Report approved by SEIAA as per Ministry's Notification S.O 3611(E) dated 25.07.2018
 - vi. Implementation of "Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016" and "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020" in case of sand mining proposals.
 - vii. Details of forest land involved in the mine lease area and availability of Stage-I/II Forest Clearance (FC) for diversion of forest land for non-forestry purpose.
 - viii. Details of Eco Sensitive Zones (ESZ) and Eco Sensitive Areas (ESAs), National Parks, Wildlife Sanctuary, Coastal Zone, Water bodies and other ecological sensitive areas within/in the vicinity of the mine lease area and if so details of NOC/Clearances obtained.
 - ix. If any Schedule-I species is present in the study area, proof of submission of Wildlife Conservation Plan to the Forest Department.
 - x. Cluster Certificate from State Mines and Geology Department.

- xi. Compliance of Hon'ble Supreme Court judgment dated 02.08.2017 passed in Common Cause vs Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014.
 - xii. Proposal of re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. in compliance to the direction dated 8th January, 2020 of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition(s) Civil No. 114/2014, Common Cause vs Union of India & Ors.
6. The provisions of this OM shall be operational subject to the outcome of Civil Appeal No. 3799-3800 of 2019 titled Union of India vs Rajiv Suri filed by Ministry before the Hon'ble Supreme Court of India against the order dated 13th September, 2018 passed in O.A. No. 200 of 2016 (Rajiv Suri Vs UOI) & order dated 21st December, 2018 passed in R.A. No. 47 of 2018 (UOI Vs Rajiv Suri).
 7. This is issued with the approval of the Competent Authority.


 (Sundar Ramanathan)
 Scientist E

To

1. The Chairperson/Member Secretaries of all the SEIAAs/SEACs.
2. The Chairman of all the Expert Appraisal Committees
3. The Chairpersons/Member Secretaries of all SPCBs/UTPCCs.
4. All the officers of IA Division

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble MEF&CC
2. PS to Hon'ble MoS, EF&CC
3. PPS to Secretary, EF&CC
4. PPS to AS (TK)/ JS(SKB)
5. Website, MoEF&CC /Guard file